JEEVIKA

THE ChangeMakers

बिहार सरकार

July 2017 • Issue 01

Redefining the Paradigms of Poverty Reduction in Bihar

बिहार में तकनीक से समृद्ध होती कृषि

Page 09

Scaling up Women's Economic Empowerment in India

Page 03

Livelihoods Generation through Traditional Art Forms

Page 13

बड़की दीदी

Page 19

From the editors desk

Greetings and a warm welcome to our very first issue of "The Changemakers "

As JEEViKA steps in the 10th year of its pledge towards poverty alleviation, it unveils its journey in the first edition of its monthly Magazine " The Changemakers" The need for sharing the initiatives of JEEViKA with our "*Didis*" (SHG women), partners, collaborators, academicia and all our well wishers was long felt. The publication of this Magazine is a step towards this thought. We commit to share, our ventures and the ethos and pathos of our "*Didis*" in their struggle against poverty.

This edition introduces Jeevika and its interventions to its audience through its **Lead Story- JEEViKA, The Journey this far…** This issue highlights the instigation of the **Bihar Transformative Development Project**, a joint venture of Government of Bihar and The World Bank with an objective to "diversify and enhance household level incomes and improve access and use of nutrition and sanitation services to 1.4million rural poor households."

The bilingual format of the magazine aims at wider circulation. The main segments that would feature regularly hence include, the **Lead Story** which would include articles related to the contemporary development interventions; "***Didi ki Kahani, didi ki zubani*"** would have stories of transforming lives of JEEViKA *Didis*;, ***Badki Didi***- a comic series with a message; **Jeevika Updates** a photo gallery of the latest events and news .

We appreciate your support and solicit your suggestions for yet another exciting venture of JEEViKA

With warmest thanks,

Mahua Roy Choudhury
mahua@brlp.in

EDITORIAL TEAM

- **Mrs. Mahua Roy Chaudhury**
  Program Coordinator (G&KM)
- **Mr. Pawan Kr. Priyadarshi**
  Project Manager (Communication)
- **Mr. Pratyush Gaurav**
  Young Professional
- **Mr. Santosh Kumar**
  Manager Communication, W.Champaran

संदेश

श्री बालामुरूगन डी. (भा.प्र.से.)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका (BRLPS)
राज्य मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

बिहार सरकार ने जिस उद्देश्य से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति का गठन किया है, उसे प्राप्त करने की दिशा में जीविका निरंतर कदम बढ़ा रही है। संस्थागत संगठनों के निर्माण से शुरू हुई यह यात्रा आज नारी सशक्तीकरण के विभिन्न आयामों को अपने में समेटे हुए है। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए सतत प्रयासरत इस परियोजना ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए वर्तमान में कुल 7000000 निर्धन परिवारों तक अपनी पहुँच बना ली है। हमारा लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2017–2018 तक 1000000 स्वयं सहायता समूह बनाकर प्रत्येक परिवार को कम से कम आजीविका संवर्द्धन की एक गतिविधि से जोड़ना है ताकि, उनका आर्थिक उन्नयन हो सके। पत्रिका के माध्यम से परियोजना के विगत 10 वर्षों की यात्रा को सरलता के साथ आम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है। हमें आशा है कि न केवल हमारा समुदाय बल्कि ग्रामीण विकास के लिए समर्पित अन्य महत्वपूर्ण संस्थान भी इससे लाभ लेकर विकास की यात्रा में अपना योगदान दे सकेंगे। मासिक स्तर पर प्रकाशित होनेवाली इस पत्रिका के माध्यम से हम समुदाय के साथ प्रभावी रूप से संवाद स्थापित कर पाएंगे। एक तरफ यह हमारी प्रगति का आइना होगा वहीँ दूसरी तरफ इसमें शामिल लेख हमारी दीदियों का मार्गदर्शन करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

CONTENTS

मौन क्रांति की ध्वजवाहिका 01

Scalling up Women's Economics Empowerment in India 03

सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण 05

प्रत्येक व्यक्ति को संस्थागत वित्तीय सेवाओं से जोड़ने का लक्ष्य 07

बिहार में तकनीक से समृद्ध होती कृषि 09

पशुधन से समृद्ध होता सूबा 09

संदेश

श्री अरविन्द कुमार चौधरी (भा.प्र.से.)
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

बिहार से गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू की गयी "जीविका" परियोजना अपने अथक एवं महत्वकांक्षी प्रयासों के फलस्वरूप आज उस मुकाम पर पहुँच गयी है जहाँ उसे किसी भी पहचान की आवश्यकता नहीं है। विगत 10 वर्षों में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत "जीविका" अपने नित नए नवाचारों के माध्यम से महिलाओं को संगठित कर उन्हें जीविकोपार्जन के नए–नए आयाम देती आ रहीहै। कल तक जो महिलायें घूंघट में छिप कर समाज की बनायी हुई रुढ़िवादी परम्पराओं एवं मान्यताओं के अनुरूप अपने जीवन का निर्वाह करने को मजबूर थीं, वही महिलायें आज समाज की मुख्य धरा से जुड़ कर आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होती जा रही हैं। प्रस्तुत पत्रिका "जीविका" के विगत एक दशक की झलकियाँ प्रदर्शित कर रही हैं जहाँ ग्रामीण महिलाओं के द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों को देखा जा सकता है। महिलाओं के जीवन में हुए परिवर्तन की रूप रेखा इस पत्रिका में विशेष रूप से उजागर किये गए हैं जो "जीविका" की इस विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह पत्रिका बिहार की उन सभी महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने अपने संगठित प्रयासों और हिम्मत के फलस्वरूप पूरे विश्व के मानचित्र पर बिहार को एक नयी पहचान दिलाई है।

CONTENTS

Livelihoods Generation Though Traditional Art Forms 13

दीदी की कहानी दीदी की जुबानी उम्मीद 15

बदलाव की बयार दियारा तक 17

बड़की दीदी 19

Bihar Rural Livelihoods Promotion Society (JEEViKA) 21

मन की कलम से 22

Events 23

मौन क्रांति की ध्वजवाहिकाएँ

"जीविका द्वारा समूह के सदस्यों एवं उनके परिजनों के स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा निधि जैसे महत्वपूर्ण गतिविधि का संचालन किया गया। साथ ही साथ गरीबों के घरों की खाद्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया।"

✍ श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा.प्र.से

बिहार में गरीबों की दयनीय स्थिति खासकर महिलाओं की दशा एवं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लगभग एक दशक पूर्व बिहार सरकार किसी ठोस कार्यक्रम की नींव रखना चाहती थी। समुचित चिंतन–मनन एवं प्रयास के बाद बिहार सरकार ने विश्व बैंक की मदद से 02 अक्टूबर 2007 को जीविका की शुरूआत की जिसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों, खासकर महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण था। जीविका का संचालन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति करती है, जो सोसाईटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अंतर्गत निबंधित है।

परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के छः जिलों–मधुबनी, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, खगड़िया तथा पूर्णिया के कुल 18 प्रखंडों में कार्य प्रारंभ किया गया और 02 अक्टूबर 2009 से इसका विस्तार उपर्युक्त जिलों के 24 अन्य प्रखंडों के अतिरिक्त मधेपुरा एवं सुपौल के एक–एक प्रखंडों में किया गया। 01 जुलाई 2010 से सुपौल एवं मधेपुरा के उपर्युक्त दो प्रखंडों को कोसी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत जीविका परियोजना में शामिल किया गया। इनके अलावा परियोजना में सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा जिले के 11 अतिरिक्त प्रखंडों में भी दिसंबर 2010 से कार्य प्रारंभ किया गया। इन 13 प्रखंडों में कोसी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के चौथे अवयव के अंतर्गत जीविकोपार्जन की पुनर्प्राप्ति तथा संवर्द्धन हेतु जीविका परियोजना में अपनाये गये सामुदायिक संस्था के मॉडल के अनुसार कार्य किया जाता रहा है।

केन्द्र सरकार द्वारा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिए जाने के उपरांत बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए जीविका को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में नामित किया गया। इसके बाद वर्ष 2012–13 में प्रथम चरण वाले छः जिलों के शेष 60 प्रखंडों। 12 अन्य जिलों के तीन–तीन प्रखंडों तथा शेष 17 जिलों के एक–एक प्रखंड में इस कार्यक्रम को लागू किया गया। अन्य 366 प्रखंडों में परियोजना का विस्तार वर्ष 2013–14 में क्रमिक रूप से किया गया। वर्त्तमान में जीविका सभी 38 जिलों के 534 प्रखंडों में कार्यरत है।

अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जीविका द्वारा आरंभ से ही ग्रामीण महिलाओं के सशक्त संगठनों यथा स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं उनके संघ का निर्माण किया जाता है। स्वयं सहायता समूहों में पंचसूत्र, ग्राम संगठन में सप्तसूत्र के अन्तर्गत नियमित बचत, आंतरिक लेन–देन, अदायगी, लेखांकन जैसी गतिविधियों को अपनाया गया है। साथ ही आवश्यकतानुसार बाहरी वित्तीय संस्थाओं के साथ उन्हें भी जोड़ा जाता है। इन गतिविधियों के साथ ही जीविका दीदियों को उनकी मांग के अनुरूप आजीविका संबंधी गतिविधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उसके लिए बहु–उद्देशीय उत्पादक समूहों का निर्माण किया जाता रहा है। इन संगठनों को आवश्यकतानुसार तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाया गया और उनके क्षमतावर्धन किया जाता रहा है जिसके कारण आज स्वप्रबंधित संस्था का विकास हुआ और वे प्रभावी सामाजिक पूंजी के रूप में विकास की भागीदार हैं।

जीविका द्वारा समूह सदस्य एवं उनके परिजनों के स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा निधि जैसे महत्वपूर्ण गतिविधि का संचालन किया गया। साथ ही साथ गरीबों के घरों की खाद्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया। इन दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम का काफी व्यापक असर हमारे लक्षित समूहों में दिखा। इन गतिविधियों के साथ समय–समय पर कई गतिविधियां समूह की दीदियों एवं उनके परिजनों के आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण के लिए आरंभ की गयी, जिसमें सबों के लिए हस्ताक्षर साक्षर होना, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास कर ग्रामीण युवाओं का विभिन्न संगठित क्षेत्रों में नियोजन, स्वास्थ्य

> जीविका दीदियों के सशक्तीकरण की शानदार मिसाल मुख्यमंत्री के शराबबंदी अभियान के क्रम में प्रमंडलीय बैठकों में दिखी, जहां जीविका दीदियों के सशक्तीकरण एवं मुखरता के मुख्यमंत्री भी कायल हो गये।

एवं पोषण कार्यक्रम, उपभोक्ता सामग्री प्राप्ति केन्द्र, श्री विधि द्वारा खेती, केंचुआ खाद निर्माण, सहभागिता किस्म चुनाव कार्यक्रम, ग्रामीण निर्धनों को दुग्ध उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मखाना उत्पादन, अगरबत्ती, मधुबनी पेंटिंग, सुजनी, बकरी पालन, मुर्गी पालन जैसे गतिविधि से जोड़कर स्वरोजगारी बनाया गया। दीदियों एवं उनके परिजनों के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें बीमित भी करवाया गया, ताकि किसी भी विपरीत स्थिति में उन्हें मदद मिल पाये।

इन सबके अलावा जीविका द्वारा आरंभ से ही गरीबी उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के साथ निरंतर अभिसरण का कार्य किया गया। सामुदायिक संगठनों एवं उसके सदस्यों के अधिकार आधारित मांग की दृष्टि से विभागीय योजनाओं के साथ अभिसरण किया गया। इसमें सरकार के विकास संबंधी कार्यक्रमों एवं सरकारी नीति के साथ परियोजना के सामंजस्य पर बल दिया गया। इनमें मनरेगा, पीएचईडी, उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि के साथ बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित कर कई कार्यों को संपादित किया जा रहा है। इसके अलावे कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भी समन्वय स्थापित कर दीदियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। जीविका द्वारा ग्रामीण नवाचारों को पहचान दिलाने के लिए बिहार इनोवेशन फोरम का आयोजन 2007 एवं 2014 में सफलता पूर्वक किया गया। इस आयोजन से कई ग्रामीण प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान किया गया।

जीविका के सफल क्रियान्वयन के लिए 6500 से ज्यादा प्रतिबद्ध कर्मी पंचायतों तक सक्रिय हैं। इनके अलावे 100 से ज्यादा यंग प्रोफेशनल जो भारत के श्रेष्ठ बिजनेस शिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण हैं, बिहार को गरीबी की दलदल से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। इन पेशेवर युवाओं ने बड़ी–बड़ी कंपनियों के स्थान पर जीविका कार्यक्रम से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन का कार्य कर रहे हैं। जीविका अपने कर्मियों के लिए पेशेवर और चुनौतीपूर्ण काम का माहौल प्रदान करता है। अनुभवी विकास कार्यकर्ताओं और महत्वाकांक्षी नवयुवकों को ग्रामीण बिहार के विकास के लिए एक दूसरे से जुड़ने का अवसर भी प्रदान किया। जीविका के विकास कार्यकर्ता उसी समुदाय के लोगों के बीच रहकर कार्य करते हैं और पारस्परिक व्यवहार द्वारा अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं। इन विकास कार्यकर्ताओं के लिए बिहार के सामाजिक क्षेत्रों की सबसे बेहतर मानव संसाधन नीति लागू की गयी है। कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए तीन स्तरों पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रखंड स्तर पर प्रखंड परियोजना क्रियान्वन इकाई, जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयन इकाई तथा राज्य स्तर पर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई सफलता पूर्वक अपने कार्यों को संपादित कर रही हैं।

जीविका ने विकास के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। अपनी विशिष्ट कार्यशैली एवं उल्लेखनीय उपलब्धियों के बल पर इसने सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं एवं अन्य हितधारकों के बीच अपनी पहचान स्थापित की है। जीविका को कई बार इसके कार्यों के लिए पुरस्कृत भी होने का अवसर मिला है, जिसमें स्कॉच अवार्ड एवं भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए दिया गया प्रमाण पत्र प्रमुख हैं। जीविका के भविष्य की योजना 2017 तक 10 लाख समूहों का निर्माण कर उससे 1.25 करोड़ परिवारों को जोड़ना है। साथ ही इन समूहों को 65000 ग्राम संगठनों एवं 1600 संकुलस्तरीय महासंघों में संगठित करना है। अब 32 जिलों के 300 प्रखंडों को जीविका–2 यानी बिहार ट्रांसफार्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त की गयी है और भविष्य की रणनीति बनायी जा रही है। इस परियोजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, महिला स्वामित्व वाली कृषि उत्पाद आधारित कंपनियों की स्थापना की जाएगी, समेकित बाल विकास कार्यक्रम का संचालन होगा साथ ही स्वच्छ भारत मुहिम के जरिए स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित कार्य किये जाएँगें।

जीविका दीदियों के सशक्तीकरण की शानदार मिसाल मुख्यमंत्री के शराबबंदी अभियान के क्रम में प्रमंडलीय बैठकों में दिखी, जहां जीविका दीदियों के सशक्तीकरण एवं मुखरता के मुख्यमंत्री भी कायल हो गये। माननीय मुख्यमंत्री जब जीविका दीदियों से रू–ब–रू हुए तो उन्होंने उनमें आये आत्मविश्वास को मौन क्रांति का नाम दिया। बिहार में शराबबंदी लागू करवाने एवं उसके सफल क्रियान्वयन में जीविका दीदियों की महत्वपूर्ण भागीदारी है। यह जीविका के गरीबी उन्मूलन मॉडल की सफलता का ही परिणाम है कि कई राज्य ने इस मॉडल को अपना रहे हैं। बिहार संसाधन सेवियों की सेवा उपलब्ध कराने हेतु कई महत्वपूर्ण राज्यों यथा–उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, असम के लिए जीविका राष्ट्रीय स्रोत संगठन की भूमिका निभा रहा है।

●

श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा.प्र.से
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

> **JEEViKA SHGs saved nearly $64 million and leveraged another $511 million from the formal financial sector. It has also significantly helped to reduce the groups' dependency on high-cost debt from moneylenders.**

Scaling up Women's Economic Empowerment in India

Ref. World Bank Blog

STORY HIGHLIGHTS

- *The World Bank's decade-long support to the Indian state of Bihar have brought transformational change to the lives of nearly seven million rural women by organizing them into self-help groups, building institutional platforms, providing access to financial services, enhancing livelihood activities, and linking them to markets.*
- *The project in Bihar inspired the government to launch the National Rural Livelihood Mission which has empowered more than 45 million women who have collectively saved $1.4 billion and leveraged $20 billion from commercial banks.*
- *More than 30 country delegations from Afghanistan, Nepal, Vietnam, Laos, Cambodia, Ethiopia, and Azerbaijan have visited NRLM projects so far to replicate the model.*

The World Bank is helping the Indian government to scale up a women's empowerment initiative in one of the poorest regions of India to bring transformational change to the lives of rural women, their families, the economy, and society.

Since 2011, the $500 million National Rural Livelihoods Project has promoted women's economic empowerment in 13 low-income states in India as part of its support to the government of India's flagship rural poverty reduction program, the National Rural Livelihood Mission (NRLM). It drew heavily on the lessons and success of the Bank-supported Bihar Rural Livelihoods Project, known as "Jeevika,"which means "livelihoods" in Hindi. Jeevika, which started in 2007 and continued into a second phase in 2016, focused on creating self-help groups for women to provide them with access to small enterprise funding, services, and public entitlements.

In the state of Bihar alone, thanks to Jeevika, there are currently nearly seven million women who are part of self-help groups. Through these groups, the women have saved nearly $64 million and leveraged another $511 million from the formal financial sector. It has also significantly helped to reduce the groups' dependency on high-cost debt from moneylenders. Before the project started, rural households in Bihar struggled to access credit from formal sources because they did not have collateral or credit history. Most importantly, in the absence of strong institutions, poor women did not have voice or agency to engage productively with local markets and face challenges to access public programs.

"Just a few years back, I was surviving on the back of a sewing machine, stitching 2-3 pieces of clothes a day with blisters on my hands," said Kiran Devi, who joined a self-help group in Bihar ten years ago and is now a director at the Aranyak Producer Company, a women-owned farmer's producer company. The company delivers better prices for more than 6,000 maize farmers in Purnia district of Bihar. She has recently purchased a tractor for $16,000, half from her own savings.

The project supports small women producers through agriculture and livestock productivity enhancement, value chain development, and non-farm activities. It helps the women to form producer groups at the village level to act as local hubs for collective training, to aggregate their produce, and to control quality. Larger women-owned producer companies undertake collective procurement through these groups and provide direct market linkage for small women farmers who previously sold to local middlemen.

"Their narrations of personal experience and efforts opened a whole new dimension," said Nitish Kumar, chief minister of Bihar. "It was a revelation to see the seeds of a deep-seated

social transformation in Bihar like never before."

The learning from the success of Jeevika contributed immensely to the launch of the National Rural Livelihoods Mission (NRLM) by the Government of India in 2011 to scale up the model across all the 30 states of the country. The NRLM so far has reached to more than 45 million women. Collectively they have saved $1.4 billion and leveraged $20 billion from commercial banks. NRLM is also supporting nearly 3.3 million women farmers to increase their productivity in agriculture and livestock.

"We are absolutely amazed at what the self-help groups have achieved," said Junaid Ahmad, World Bank's Country Director in India during his recent visit to the NRLM program in the low-income state of Jharkhand. "It is remarkable to see how these women groups are able to manage their fast-expanding role in the area's economy, while demanding, and receiving, better services from local governments to strengthen their functioning. It is beyond what we can define in the World Bank as women's empowerment."

The project is applying an innovative approach to build a large cadre of community resource persons to help the scaling across 30 states.

"155,000 women who have come out of poverty are the greatest agents of change in promoting sustainable agriculture, providing banking services, developing a cadre of veterinarians for animal care, bookkeepers, and accountants but most importantly agents for social transformation in villages," said Amarjeet Sinha, Secretary, with the ministry of rural development, Government of India.

These empowered women then identify and mobilize other poor women into self-help groups and provide them with microcredit savings and loans, help them make plans so they can escape poverty too.

Parmesh Shah, the task team leader for the National Rural Livelihoods Project, said scaling up is centered on an ecosystem approach to develop new engagement, solutions, and alliances to meet the client demand for high-quality technical assistance, adoption of high impact innovations, and quality capacity building of more than 10,000 professionals.

In order to scale up the project, the World Bank has applied a series of unique interventions such as organizing an 'Innovation Forums' that enabled innovations by the public, private and social enterprise sectors across many livelihood areas to be systematically identified and scaled up through the program across states. NRLP has also set up a learning alliance that allows states like Andhra Pradesh, Bihar, Tamil Nadu, and Kerala to share experience and to help other low-income states to scale up the model. And finally, a human resource policy has introduced the hiring of young graduates from leading management institutes.

The National Rural Livelihoods Mission is providing important lessons to other Bank projects in Africa and East Asia. More than 30 country delegations from Afghanistan, Nepal, Vietnam, Laos, Cambodia, Ethiopia, and Azerbaijan have visited the Indian states where the project succeeded to replicate the model. ●

(World Bank Blog)

सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण

सामुदायिक साधन सेवी के रूप में परियोजना के पास एक बहुत बड़ी फौज है जो पुराने समूह की प्रशिक्षित सदस्य होती है। जिनका काम परियोजना के नए क्षेत्रों में समूह गठन से लेकर उन्हें प्रशिक्षण देना होता है। वहीं संकुल स्तरीय संघ के स्तर पर समुदाय के द्वारा स्वप्रबंधित प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र की भूमिका अति महत्वपूर्ण है जहाँ समुदाय सम्बंधित सभी प्रकार के प्रशिक्षणों की समुचित व्यवस्था होती है। इसका प्रबंधन स्वयं समुदाय के द्वारा ही किया जाता है।

राजीव रंजन

किसी देश या राज्य की सबसे बड़ी पूंजी उसका मानव संसाधन होता है। जब हम जन समूह से किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति की आशा करते हैं तब हमें संस्था निर्माण की आवश्कयता होती है। इस विशेष उद्देश्य की प्राप्ति में संस्थाओ का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना की संस्था में शामिल लोगों का क्षमतावान होना।

जीविका परियोजना में सामुदायिक संस्थानों का निर्माण सबसे प्रमुख गतिविधि है। इसके तहत तीन प्रकार के सामुदायिक संस्थानों का गठन किया जाता है। "समूह में शक्ति है" को सूत्र वाक्य मानते हुए परियोजना अपने बृहत्तर उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सबसे पहले समान आर्थिक एवं सामाजिक स्तर के 10–15 महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह बनाती है। फिर 15 से 25 समूहों को मिला कर एक ग्राम संगठन बनाया जाता है। इसके बाद 25 से 40 ग्राम संगठनों को मिलाकर सर्वोच्च स्तर की इकाई संकुल स्तरीय संघ का गठन किया जाता है। इन तीन संगठनों के अतिरिक्त एक अन्य संगठन जिसे उत्पादक समूह कहा जाता है, इसका गठन आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के उद्देश्य से किया जाता है।

कोई भी वैधानिक संस्था अपने अस्तित्व में आने के साथ ही अनेक आवश्यक नियमों के आबद्ध हो जाते हैं. यह बात उपरोक्त सभी संगठनों पर भी लागू होती है। समूह बनने के साथ ही उसके कुशल संचालन के लिए उनमे पंचसूत्र के नियमों का पालन अनिवार्य हो जाता है। इसके तहत नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित लेन–देन, नियमित ऋण वापसी एवं लेखा–जोखा जैसे नियम समूह के लिए अनिवार्य व्यवहार नियम होते हैं। प्रत्येक समूह लोकतान्त्रिक विधि से समूह के सफल संचालन के लिए तीन पदाधिकारियों, अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव करते हैं जो, समूह से सम्बंधित अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। समूह की साप्ताहिक बैठकों में समूह स्तर के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होती है,आम सहमती बनती है एवं सदस्यों की छोटी मोटी आवश्कताओं की पूर्ति होती है. जैसे–जैसे समूह पुराना होता है उसके सदस्यों की जरूरतें भी बड़ी होती जाती है। इस बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़े मंच की आवश्कता महसूस होती है। एक ऐसा मंच जो सदस्यों की बढ़ती आवश्कताओं की पूर्ति कर सके।

इसी उद्देश्य से 15 से 25 समूहों को मिलाकर एक ग्राम संगठन बनाया जाता है। एक ग्राम संगठन में शामिल प्रत्येक समूह के तीन पद धारी इसके सदस्य होते हैं। ग्राम संगठन के सफल संचालन हेतु यहाँ भी लोकतान्त्रिक विधि से पांच पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त ग्राम संगठन में उपाध्यक्ष एवं उपसचिव भी होते हैं। समूह से जुड़े विभिन्न मुद्दों एवं आवश्यकताओं के आकलन एवं मुल्यांकन के लिए ग्राम संगठन में विभिन्न प्रकार की उप समितियां बनी होती हैं जो ग्राम संगठन की बैठक में जरूरत के मुताबिक अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है. एक नवगठित ग्राम संगठन माह में एक बार बैठक करता है जो की आगे चलकर पाक्षिक बैठक में तब्दील हो जाता है। इस प्रकार किसी एक गाँव में सामान्यतया एक से दो ग्राम संगठन हो सकता है। ग्राम संगठन के स्तर पर परियोजना द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम उनमे से महत्वपूर्ण हैं। ग्राम संगठन की बैठकों में समूह से प्राप्त मांगों, आवश्कताओं एवं भविष्य में होने वाली गतिविधियों पर गहराई से चर्चा कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। हम कह सकते हैं कि ग्रामीण स्तर की समस्याओं एवं जरूरतों की पूर्ति हेतु ग्राम संगठन एक मजबूत मंच के भांति कार्य करता है। ग्राम संगठन की सभी सदस्यों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो पाए, इस उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष ग्राम संगठन के पदाधिकारियों को चुनाव के माध्यम से बदला जाता है।

जब उद्देश्य बहुत बड़ा हो, जिसका प्रभाव प्रखंड स्तर तक पड़े एवं जिससे एक बड़ा समुदाय प्रभावित होता हो, तब बात संकुल स्तरीय संघ की आती है। एक संकुल स्तरीय संघ में 25 से 40 ग्राम संगठन शामिल होते हैं। प्रत्येक ग्राम संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव इसके कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। दिन प्रतिदिन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इसके पदाधिकारियों का चयन भी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है।

संकुल स्तरीय संघ का कार्य एवं अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। यह अनुबंधित संस्था अपने सदस्यों के हित के लिए सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के बीच सेतु का काम करता है। सदस्यों के वित्तीय एवं बीमा संबंधी जरूरतों की पूर्ति के अलावे यह संस्थान ग्राम संगठन स्तर की सभी गतिविधियों का अनुश्रवण एवं मुल्यांकन करता है। सदस्यों की आजीविका संबंधी गतिविधियों को ग्राम संगठन के माध्यम से आगे बढाता है. अपने अंगीकृत ग्राम संगठनों में इच्छित गतिविधि के संपादन हेतु राशि की उपलब्धता को सुनिश्चित करना संकुल स्तरीय संघ की जिम्मेदारी होती है। जीविका परियोजना का मूल उद्देश्य संस्था निर्माण कर उसका क्षमतावर्धन करना है ताकि ग्रामीण महिलाओं को अपने अधिकार के प्रति जागरूक किया जा सके. सदस्यों का क्षमतावर्धन करने के लिए परियोजना में एक समर्पित प्रशिक्षण प्रणाली आरम्भ से ही स्थापित है जो विभिन्न स्तरों पर सभी संस्थानों के सदस्यों के क्षमतावर्धन का कार्य करती है। समुदाय आधारित आजीविका के विभिन्न अवयवों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से न केवल समूह के सदस्यों का क्षमतावर्धन किया जाता है बल्कि विभिन्न स्तर के संस्थानों के कुशल प्रबंधन में शामिल सभी प्रकार के सामुदायिक साधन सेवियों को भी अनिवार्य रूप से क्षमतावान बनाया जाता है। इसी विशिष्ट गुण के कारण परियोजना की अपनी विशिष्ट पहचान है. समूह गठन के साथ ही सदस्यों के क्षमतावर्धन हेतु मोडूलर प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य समूह क्यों, गरीबी के कारण, गरीबी का दुष्चक्र जैसी महत्वपूर्ण बातों के प्रति सदस्यों को संवेदनशील बनाना होता है। ग्राम संगठन के गठन का उद्देश्य उसके कार्य एवं जिम्मेदारी जैसे दूसरे

महत्वपूर्ण बातों को ग्राम संगठन के प्रशिक्षण में बतलाया जाता है। परियोजना द्वारा समय समय पर जरूरत के हिसाब से विभिन्न माध्यमों के द्वारा नयी नयी गतिविधियों पर महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है।

समूह गठन, समूह की आदर्श बैठक,लेखांकन की पुस्तिकाओं का संधारण, बैंकिंग लेन–देन, नवीनतम कृषि तकनीक, गैर कृषि गतिविधि, न्यूनतम वित्तीय साक्षरता, क्रय विक्रय, कौशल विकास इत्यादि जैसे तमाम गतिविधियों के लिए समूह के सदस्यों के साथ साथ उसके साधन सेवियों को भी सघन रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।

सामुदायिक साधन सेवी (C R P) के रूप में परियोजना के पास एक बहुत बड़ी फौज है जो पुराने समूह की प्रशिक्षित सदस्य होती है। जिनका काम परियोजना के नए क्षेत्रों में समूह गठन से लेकर उन्हें प्रशिक्षण देना होता है. वहीँ संकुल स्तरीय संघ के स्तर पर समुदाय के द्वारा स्वप्रबंधित प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र की भूमिका अति महत्वपूर्ण है जहाँ समुदाय सम्बंधित सभी प्रकार के प्रशिक्षणों की समुचित व्यवस्था होती है। इसका प्रबंधन स्वयं समुदाय के द्वारा ही किया जाता है।

समुदाय आधारित इस व्यवस्था के जरिये महिलाओं के सशक्तिकरण और सामजिक तथा आर्थिक तरक्की की इमारत धीरे–धीरे पूरे बिहार में बुलंदी की कगार पर है। इसका सकारात्मक प्रभाव हर गरीब महिला की मुस्कान बन छा रही है।

✍ **राजीव रंजन** प्रबंधक संचान, समस्तीपुर

प्रत्येक व्यक्ति को संस्थागत वित्तीय सेवाओं से जोड़ने का लक्ष्य

> वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में जीविका की पहल से महिलाओं को महाजन के चंगुल से छुटकारा मिल रहा है और उनमें स्वच्छ बैंकिंग की आदत विकसित हो रही है।
>
> ✍ श्री संतोष कुमार

वित्तीय समावेशन का अर्थ एवं उद्देश्य : प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण तरीके से संस्थागत वित्तीय गतिविधियों से जोड़ना, वित्तीय समावेशन कहलाता है। वित्तीय समावेशन के प्रमुख 5 घटक हैं– 1. बैंक में बचत खाता होना 2. समय पर आवश्यकतानुसार ऋण की प्राप्ति 3. रेमिटेंस (बैंक खातों के जरिये रुपये का हस्तांतरण) 4. बीमा और 5. पेंशन।

जीविका परियोजना के अंतर्गत वित्तीय समावेशन पर खास जोर दिया गया है। चूंकि, ग्रामीण क्षेत्रों में आधी से ज्यादा आबादी के पास अपना कोई बैंक खाता नहीं है। परिणामस्वरूप वे न केवल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से महरुम हैं बल्कि उन तक सरकारी योजनाएं भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने 2020 तक देश की संपूर्ण आबादी को बैंकों से जोड़ने और सभी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।

समूह का गठन एवं बचत : महिलाओं में आई वित्तीय जागरूकता : जीविका परियोजना ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए काम करती है। यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले समान स्तर की 10–12 गरीब महिलाओं को मिलाकर एक समूह का गठन किया जाता है। समूह से जुड़ीं सभी महिलाएं एक समान रूप से हर सप्ताह नियमित बचत करती हैं। सामूहिक बचत से एकत्रित धनराशि से समूह की दीदियां अपनी छोटी–छोटी जरूरतें पूरी करती हैं और इसके बदले उन्हें 2 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से ब्याज अदा करना पड़ता है। वे किस्त दर किस्त ऋण का नियमित भुगतान करती हैं। इससे समूह में महिलाओं के बीच आपसी लेनदेन को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही इससे प्राप्त ब्याज से समूह की आमदनी होती है। दूसरी तरफ महिलाओं को महाजन के चंगुल से भी छुटकारा मिलता है और उनमें स्वच्छ बैंकिंग की आदत विकसित होती है। इन पैसों के लेनदेन का पूरा हिसाब–किताब लेखांकन पद्धति के अनुसार रखने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। इस तरह से ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय जागरूकता का स्तर बढ़ा है।

बैंक से जुड़ाव : बैंकों में बचत खाता :समूह की अवधि तीन माह होने पर समूह का बैंक में बचत खाता खुलवाया जाता है। बचत खाता खुलने से समूह की सदस्यों द्वारा एकत्रित की गई बचत की राशि जमा कर रखी जाती है। बैंकों में बार–बार राशि जमा करने या इसे निकालने से वे बैंकिंग कार्यप्रणाली से अवगत होती हैं। संपूर्ण वित्तीय समावेशन के तहत समूह से जुड़ी महिलाओं का व्यक्तिगत खाता खोलने का भी अभियान चलाया गया। इससे काफी संख्या में महिलाओं का बैंकों में अपना बचत खाता खुला। उनका बैंक खाता खुलने से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में मिलना संभव हो पाया है।

सूक्ष्म नियोजन : बैंक खाता खुल जाने के बाद समूह के प्रत्येक सदस्यों का सूक्ष्म नियोजन किया जाता है। सूक्ष्म नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समुदाय अपनी समस्त जरूरतों का आकलन करता है और सदस्य, समूह एवं संगठन के स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय लेता है और संसाधनों का समुचित उपयोग होता है।

प्रारंभिम पूंजीकरण – समूह का सूक्ष्म नियोजन होने के बाद प्रखंड परियोजना कियान्वयन इकाई में गठित ऋण समिति की बैठक होती है, जिसे एलसीएम कहते हैं। इसमें माइक्रो प्लानिंग एवं आईसीएफ के लिए आवेदन पर विचार किया जाता है। इसके बाद जीविका परियोजना समूह को शरूआत में आरंभिक पूंजीकरण निधि (आईसीएफ) के रूप में 60,000 रुपये और परिकर्मी निधि (रिवॉल्विंग फंड) के तौर पर 15,000 रुपये प्रदान करती है। इस राशि से समूह की दीदियां आजीविका शुरू करने या कोई अन्य आवश्यक जरूरतें पूरी करती हैं।

बैंक क्रेडिट लिंकेज : आवश्यकतानुसार ऋण की प्राप्ति : समूह के सदस्यों की जीविकोपार्जन संबंधी और अन्य आवश्यक जरूरतों की पूर्ति केवल बचत के पैसे से नहीं की जा सकती है। ऐसे में समूह को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। समूह को बैंक से ऋण की पहली किस्त के

> महिलाओं के बचत खाता खुलने से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में मिलना संभव हो पाया है

तौर पर 50,000 रुपये मिलते हैं। इन पैसों से समूह की दिदियां अपनी जीविकोपार्जन संबंधी जरूरतें पूरी करती हैं। वहीं प्रत्येक माह ऋण खातों का सही संचालन होने की स्थिति में एक साल के उपरान्त बैंक ऋण की दूसरी किस्त के तौर पर 1 लाख से 1.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। समूह की साख अच्छी होने की स्थिति में कई बैंक ऐसे समूहों को ऋण की तीसरी किस्त भी प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है।

आजीविका : समूह की दीदियां अपनी बचत राशि, जीविका से प्राप्त प्रारंभिक निवेश राशि की राशि और बैंक से प्राप्त ऋण का उपयोग स्वरोजगार के लिए छोटे–मोटे व्यवसाय शुरू करने, कृषि कार्य, पशुपालन, मुर्गीपालन आदि कार्य करने के लिए करती हैं, जिससे उनके घर की आमदनी बढ़े। आजीविका से होने वाली कमाई से वे कर्ज का नियमित भुगतान कर रही हैं। यही कारण है कि बैंकों द्वारा जीविका के स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऋण में एनपीए (गैर निष्पादित परिसंपत्ति) की दर बहुत कम है। इससे तमाम बैंकों के बीच जीविका समूह की साख बहुत अच्छी है।

बीमा : आम आदमी बीमा योजना के तहत समूह से जुड़ी महिलाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। योजना के मुताबिक बीमा के प्रीमियम का भुगतान सरकार और सदस्यों के द्वारा मिलकर किया जाता है। प्रीमियम की कुल राशि प्रतिवर्ष 200 रुपये है। इसमें से सदस्यों से 100 रुपये का अंशदान लिया जाता है जबकि प्रीमियम के लिए शेष 100 रुपये का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है। जून 2016 तक के आंकड़ों के मुताबिक इस समय परियोजना के तहत समूह से जुड़ी 8,09,021 महिलाओं का बीमा

JEEViKA's Insurance Progress

Enrolment of SHG members

Death Claim Vs Claim Settled

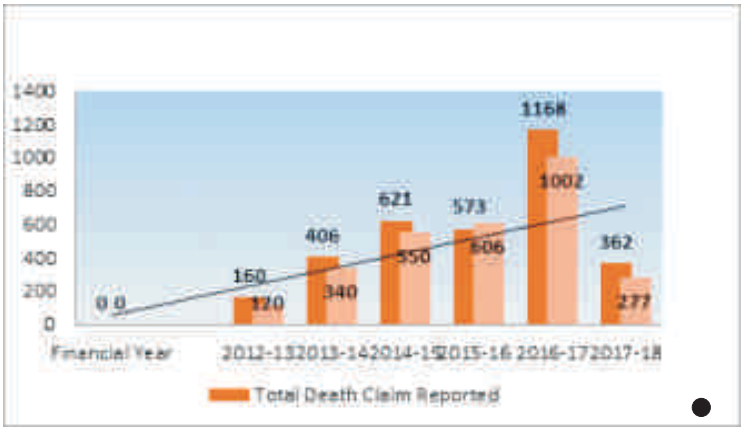

श्री संतोष कुमार
संचार प्रबंधक, पश्चिम चंपारण

बिहार में तकनीक से समृद्ध होती कृषि

श्री राजीव रंजन

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार की सत्तर प्रतिशत आबादी के मुख्य आय का जरिया कृषि है। हालांकि ज्यादातर किसानों के पास खेती करने को बहुत अधिक अपने खेत नहीं है। वो या तो बटाई की खेती करते है या फिर पैसों के बदले खेत लेकर अपनी किस्मत आजमाते है। उन्नत कृषि तकनीक और सिचाईं की उपयुक्त व्यवस्था न होने के कारण बिहार में कृषि भाग्य भरोसे ही होती है। अगर किसी तरह पैदावार अच्छी हो भी जाये तो उचित मूल्य पर बिक्री बड़ी समस्या बन जाती है। फसलों के भंडारण और विपणन की समस्या के कारण भी किसानो को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।

ऐसे में जीविका ने बिहार में किसानों को नई तकनीक और उन्नत खेती के जरिय समृद्ध बनाने के सफर की शुरुआत 2007 में की। किसानों के साथ बैठकों के माध्यम से उन्हें नई तकनीक और विधि की जानकारी दी गई। इसी कड़ी में 'प्रदान' की सहायता से श्री विधि से धान की रोपाई की शुरुआत 2009 में हुई। जिसके बाद बिहार सरकार ने वर्ष 2010 को श्री विधि वर्ष घोषित कर दिया। श्री विधि के जरिये किसानों ने कम मेहनत में अच्छी और दमदार फसल उपजाई और फिर इसी तकनीक से उपजी गेहूँ की फसल भी किसानों की किस्मत बदलने लगी। जीविका ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिय दो तरह से कार्य करना प्रारम्भ किया, जिसमें पहला है अच्छी पैदावार और दूसरा है पैदावार का अच्छा मूल्य। अच्छी पैदावार के लिय किसानों को कई तरह के प्रशिक्षण और नई तकनीक की जानकारी दी गई। छोटे–छोटे हिस्सों में वैज्ञानिक तरीके से खेती करके उनके सुखद परिणामों से अवगत कराया गया। कम जमीन और कम खर्चो में अच्छी पैदावार के लिय खेतों की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए इसको किसानों के सहयोग से तैयार करके बताया जाता है, ताकि किसान इसे अच्छी तरह समझ सकें। इसके लिय जीविका कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालयों और आत्मा जैसी संस्थाओ की मदद से किसानों को बेहतर पैदावार के गुण सिखाती है। हालांकि वर्षों पुरानी परम्परा को छोड़ एक

जीविका ने बिहार में किसानों को नई तकनीक और उन्नत खेती के जरिय समृद्ध बनाने के सफर की शुरुआत 2007 में की। किसानों के साथ बैठकों के माध्यम से उन्हें नई तकनीक और विधि की जानकारी दी गई। जिसके बाद बिहार सरकार ने वर्ष 2010 को विधि वर्ष घोषित कर दिया।

झटके में आधुनिक खेती को अपनाना किसानों के लिय आसान नहीं था। पारम्परिक खेती से जो नतीजे किसानों को मिलते थे उससे वो संतुष्ट तो नहीं थें फिर भी इसमे परिवर्तन को किसान आसानी से तैयार नही थे। इसके लिय महिलाओ के स्वयं सहायता समूहों की मदद ली गई। जिनके माध्यम से किसानों को खेती के बारे में विस्तृत जानकारी बैठकों के द्वारा दी गई। जीविका ने किसानों को दो तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने का रास्ता दिखाया। जिसमें पहला है, रसायनिक खादों का प्रयोग न करना तथा दूसरा है अन्न का उचित मूल्य।

इसके लिय महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना की वर्ष 2012 में शुरुआत की गई। जिसमे बिहार के 9 जिलों के 15 प्रखंडो में इसकी शुरुआत की गई। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का उद्देश्य किसानों को कम कीमत पर अच्छी उपज के साथ ही किसानों की उपज का सही मूल्य मिलें इसकी भी कोशिश उत्पादक समूहों और उत्पादक कम्पनी के माध्यम से की जाती है। इसके तहत जैविक खेती के बारे में लोगो को इसके माध्यम से जानकारिया दी गई। जीवामृत, निमास्त्र के द्वारा जैविक खेती करने के तकनीक से किसानों को जोड़ा गया। इससे उन्हें दोहरा लाभ होने लगा। एक तरफ तो रसायनिक खाद के उपर हो रहे खर्च से किसानों को मुक्ति मिली तो दूसरी तरफ फसलों की पैदावार भी अच्छी होने लगी। इस परियोजना के तहत अब तक एक लाख उन्नीस हजार किसानों को जोड़ा जा चूका है। जीविका द्वारा किसानों को कई तरह से कृषि को उन्नत बनाने के लिय प्रशिक्षित किया जाता है,जिसमे कुछ प्रमुख है।

वैज्ञानिक तरीकों से सब्जियों का उत्पादन– किसानों के आमदनी को बढ़ाने के लिय जीविका ने सब्जियों के उत्पादन में भी वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की पहल की गई। किसानों को कृषि संस्थाओ के साथ मिलकर प्रशिक्षित किया गया और उन्हें मौसम के अनुकूल सब्जियों के उत्पादन के गुण बताये गए। इसका काफी व्यापक असर पड़ा और तकनीक आधारित खेती किसानों के लिय वरदान साबित होने लगी है।

पोषण युक्त आहार का आधार किचेन गार्डन– गरीब परिवारों के लिय छोटी सी जमीन से पुरे परिवार का पोषण युक्त भोजन का सपना पूरा कर रहा है किचेन गार्डन। केवल बीस फिट के आयताकार खेत में रोजाना प्रयोग होने वाली घरेलू सब्जियों का उत्पादन किसानों के लिय काफी लाभप्रद है। भिन्डी, करेला, तरोई, मिर्ची, टमाटर, साग जैसे कई सब्जियों का पुरे वर्ष न्यूनतम खर्च पर उत्पादन हो रहा है। जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओ और बच्चों को रोजाना हरी एवं पोषण युक्त सब्जिया मिल रही है। कम मेहनत और कम लागत होने की वजह से किचेन गार्डन बहुत लोकप्रिय हो रहा है।

विपणन के लिय उत्पादक समूह है सक्रिय – किसानों के उत्पादों को बेहतर बाजार मूल्य के लिय जीविका में उत्पादक समूह का गठन किया गया है। उत्पादक समूह एक स्व–प्रबंधित व्यवसायिक संगठन है। जिससे जुड़े सदस्य उत्पादकता, बाजार संबंधता का कार्य उत्पादक समूह के माध्यम से करते है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य विपणन के माध्यम से दिलाना है।

इसी तरह जीविका पुरे बिहार में आधुनिक कृषि के माध्यम से किसानों को अच्छी आमदनी और बेहतर उत्पादन के लिय जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। इसमें कोई संदेह नही है की आने वाले कुछ सालों में जीविका किसानों के साथ मिल कर बिहार में तकनीक आधारित कृषि को नया आयाम देते हुए इतिहास रचेगी।

श्री राजीव रंजन
संचार प्रबंधक, औरंगाबाद

पशुधन से समृद्ध होता सूबा

✍ श्री रवि शंकर

जीविका का मुख्य उद्देश्य निर्धनों के आजीविका स्रोत को बेहतर बनाना है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में 4–5 मुख्य जीविकोपार्जन क्षेत्र है जिससे सामुदायिक सदस्यों को जोड़कर उनके विकास के लिए चिरस्थायी आजीविका स्रोत को सृजित किया जा सकता है। कृषि, पशुधन एवं डेयरी, बिहार में उपलब्ध कुछ प्रमुख क्षेत्र है जिसमें परियोजनान्तर्गत जीविकोपार्जन संबंधी कार्य किये जाते हैं।

1. डेयरी (दुग्ध उत्पादन)

दूध उत्पादन एवं दुग्ध आधारित आजीविका गतिविधियों का संचालन मवेशी एवं दुधारू पशुओं के पालन का मुख्य उद्देश्य है। परियोजनान्तर्गत डेयरी तथा दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में निम्न कार्य किये जा रहे है।

DCS का गठन – DCS अर्थात डेयरी कोआपरेटिव सोसाइटी छोटे स्तर पर गठित डेयरी समितियाँ है जो दुग्ध उत्पादन, वितरण एवं विपणन संबंधी कार्य करती है जिससे दूध एवं सम्बंधित उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। परियोजना द्वारा स्वयं सहायता समूहों तथा ग्राम संगठनों को डेयरी कोआपरेटिव सोसाइटी के गठन हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। यह समितियाँ बिहार राज्य कोआपरेटिव दुग्ध महासंघ (COMFED) से सम्बद्ध है। अब तक कुल 291 DCS जीविका द्वारा संचालित किये जा रहे है। जीविका द्वारा दूध उत्पादन बढ़ाने तथा पशुओं के संरक्षण संबंधी निम्न कार्य किये जाते हैं।

(क) जानवरों का टीकाकरण – (HS] BQ) खुरहा एवं मुँहपका रोग (FMD) के रोकथाम हेतु साल में दो बार तकनीकी ढंग से मिनाशक देकर जानवरों का टीकाकरण किया जाता है ।

(ख) शिक्षण एवं प्रशिक्षण – दूघ उत्पादन की लगभग 75 फीसदी लागत जानवरों के चारे पर खर्च राशि पर आधारित होता है। अतः दुधारू पशुओं का आहार अर्थात चारा, उसकी उपलब्धता, कीमत एवं गुणवत्ता दुग्ध व्यवसाय से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जीविका द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये पशु–पालकों को उन्नत एवं बेहतर चारा संबंधी प्रशिक्षण, हरे चारे की महत्ता, सूखे तथा कम पौष्टिक पशु आहार को तकनीक के द्वारा बेहतर चारा बनाने संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है।

आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम (Infrastructure Development Programme)– इसके अंतर्गत स्वचालित दुग्ध संग्रह इकाई (Automated Milk Collection Unit) स्थापित किये जाते हैं जिससे दुग्ध क्रय प्रक्रिया, कम समय में वसा निरीक्षण एवं दुग्ध उत्पादकों को स्पॉट पेमेंट जैसी सुविधाएं प्रदान की जा सकें। कुल 250 AMCU जीविका द्वारा संचालित किये जा रहे हैं ।

अभिसारिता कार्यक्रम (Convergence with different programmes) – इसके अंतर्गत राज्य संचालित भिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम जैसे लघु डेयरी, मीनी डेयरी की स्थापना करके, दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी करने का

प्रावधान जीविका मॉडल में डेयरी गतिविधि के अंतर्गत किया गया है।

2. बकरी पालन

बकरी पालन प्रायः सभी जलवायु में कम लागत, साधारण आवास, सामान्य रख–रखाव तथा पालन–पोषण के साथ संभव है। इसके उत्पाद की बिक्री हेतु बाजार सर्वत्र उपलब्ध है। इन्हीं कारणों से पशुधन में बकरी का एक विशेष स्थान है।

आज जब एक ओर पशुओं के चारे–दाने एवं दवाई महँगी होने से पशुपालन आर्थिक ष्टि से कम लाभकारी हो रहा है वहीं बकरी पालन कम लागत एवं सामान्य देख–रेख में अपने गुणों के कारण गरीब किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के जीविकोपार्जन का एक लोकप्रिय साधन बन रहा है। इतना ही नहीं इससे होने वाली आय समाज के आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बकरी पालन स्वरोजगार का एक प्रबल साधन बन गया है।

बिहार के चार जिलों पश्चिम चंपारण, रोहतास, अररिया और नवादा के बगहा–2, रोहतास, रानीगंज एबं रजौली प्रखंड में जीविका द्वारा बकरी पालन कार्य का आरंभ किया जा चुका है। इसमें अभी तक 12 उत्पादक समूहों का गठन किया जा चुका है और पशु सखी (Cadre) का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

3. मुर्गीपालन

जीविका एक जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति है अतः आजीविका तथा जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्यों को इसमें समान एवं उचित प्राथमिकता दी गयी है। इसी उद्देश्य के अंतर्गत बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग अर्थात घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन क्रियाकलाप की संकल्पना की गयी है। उक्त गतिविधि का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को अतिरिक्त आय स्रोत से जोड़ने के साथ उनके परिवार से कुपोषण को समाप्त करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के घर तक रोजगार का अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराना, स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए चिर–स्थायी जीविकोपार्जन विकल्प स्थापित करना, प्रवजन रोकना, पोषण के स्तर को बेहतर बनाना इसके प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य है।

बिहार सरकार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा निर्गत राज्यादेश के आलोक में समेकित मुर्गी विकास योजना का संचालन परियोजना द्वारा किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की व्याख्या की गयी है जो गतिविधि के सफल क्रियान्वयन के निमित्त उद्धरित है।

चूजों का दो स्तरों पर पालन – पहला 28 दिनों तक मदर यूनिट स्तर पर, इसके बाद दूसरा लाभुक स्तर पर जहाँ चूजों का वितरण किया जाता है। लाभुको को एक पिंजरे के साथ 150 चूजें 6 चरणों में दिया जाता है। पहले 28 दिनों में मदर यूनिट स्तर पर चूजों का तकनीकी विधि द्वारा रख रखाव एवं टीकाकरण किया जाता हे। परिवारिक अथवा लाभुक स्तर पर चूजों की अच्छी तरह से देखभाल हेतु PRP (पोल्ट्री रिसोर्स पर्सन) की सुविधा दी जाती जो एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है। अभी तक कुल 421 मदर यूनिटों की स्थापना की जा चुकी है जिससे 126786 परिवार लाभान्वित हुए है।

4. पशु जागरूकता शिविर

जीविका में पशुओं के स्वास्थ्य एवं संवर्द्धन हेतु दो तरह के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

(क) पशु स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर– इसके अंतर्गत बड़े पशुओं के स्वास्थ्य की जाँच तथा उपयुक्त दवाई का वितरण शिविर के माध्यम से किया जाता है। साथ ही पशुओं के रख–रखाव तथा खानपान संबंधी जानकारी दी जाती है। अभी तक कुल 142 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है।

(ख) छोटे जानवरों का स्वास्थ्य एवं टीकाकरण शिविर– इसके अंतर्गत भेड़–बकरियों का PPR जैसी घातक बिमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण किया जाता हे। साथ इनके स्वास्थ्य की जाँच, रख–रखाव तथा खानपान की जानकारी दी जाती है। अभी तक कुल 75 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है।

✍ **श्री रवि शंकर** संचार प्रबंधक, रोहतास

Livelihoods Generation through **Traditional Art Forms**

Mr. Biplab Sarkar

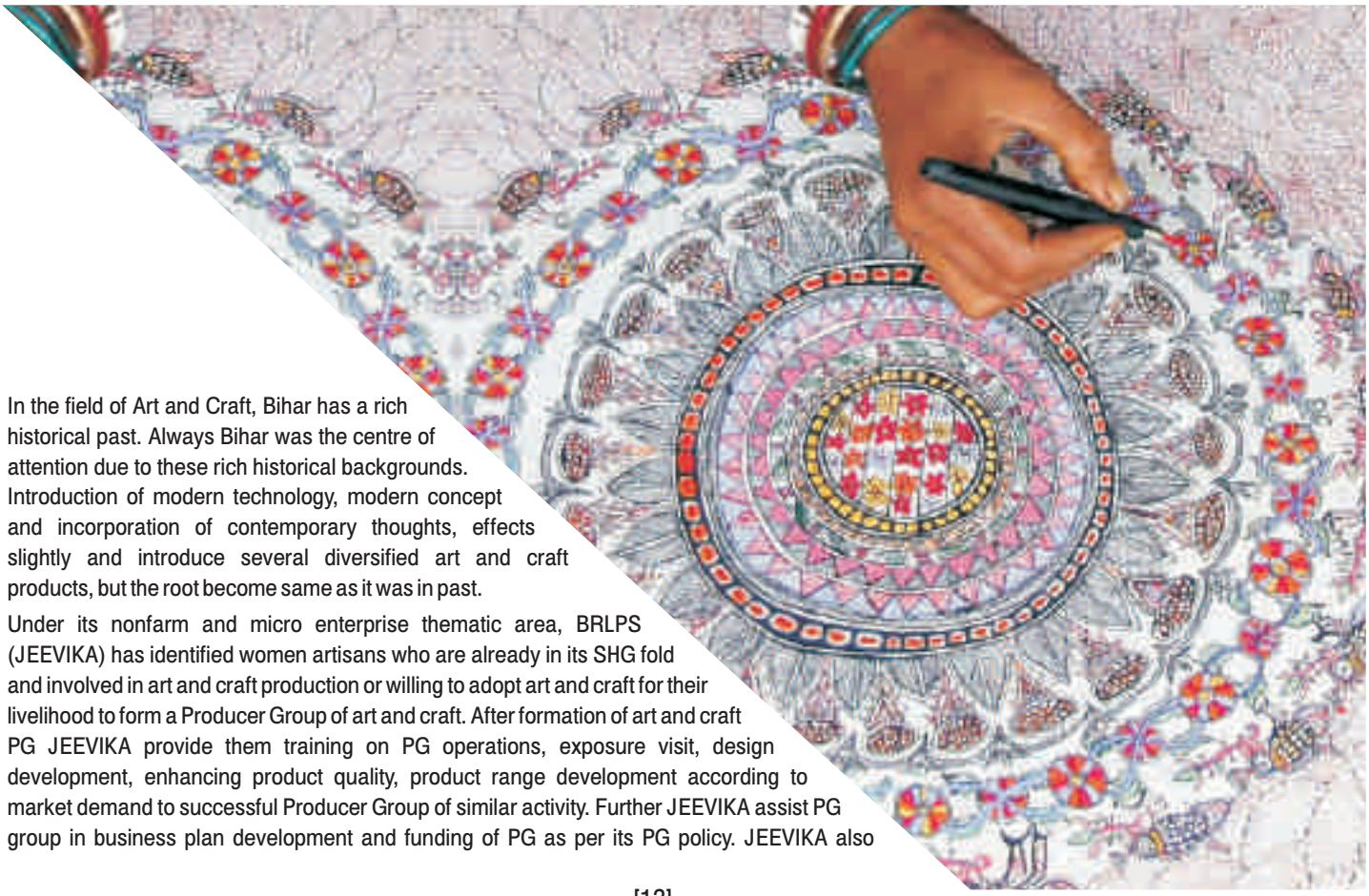

In the field of Art and Craft, Bihar has a rich historical past. Always Bihar was the centre of attention due to these rich historical backgrounds. Introduction of modern technology, modern concept and incorporation of contemporary thoughts, effects slightly and introduce several diversified art and craft products, but the root become same as it was in past.

Under its nonfarm and micro enterprise thematic area, BRLPS (JEEVIKA) has identified women artisans who are already in its SHG fold and involved in art and craft production or willing to adopt art and craft for their livelihood to form a Producer Group of art and craft. After formation of art and craft PG JEEVIKA provide them training on PG operations, exposure visit, design development, enhancing product quality, product range development according to market demand to successful Producer Group of similar activity. Further JEEVIKA assist PG group in business plan development and funding of PG as per its PG policy. JEEVIKA also

sponsor PG in different fair and exhibition so that they can showcase their products and an opportunity to get order from market. JEEVIKA provide handholding support to PG group so that they can become a self sustainable group over a period of time.

Institutional frame work

Activity mapping & mobilization of SHG members to form a Producer Group

Business plan development & Financial support

Training on production techniques & value addition

Bulk procurement, production & sells. Payment made to producers group

Non Farm Interventions

JEEViKA, under the non-farm theme is involved in promoting various rural non-farm activities that include incense stick, jute, bee keeping for honey, Jute rope, Madhubani Painting, Sikki craft, Aplique Art, Sujani, Blankets, Carpet, Bangles, etc.

Collaboration for Skilling, Training and Marketing

A brief story about JEEViKA Product

MADHUBANI-PAINTINGS : Madhubani painting, originally known as Mithila or Maithili painting, is traditionally a form of *bhitti-chitra* or wall art. Mithila painting is a tradition of the ancient Mithila region. JEEViKA started working with the artisan of Madhubani and formed a PG name Shilp Sangh at Rajnagar Block of Madhubani District. With the group formed merely with 8 members, now it has grown to involve artisans to a total of 40 members.

SIKKI : Sikki crart is made from grasses namely sikki, munj and khar. Sikki Jeevika Gram Sangathan, a Producer group located in a remote village called Raiyam in Madhubani district of North Bihar, is a group comprising of skilled women artisans involved in traditional Sikki art. Initially starting with merely 15 selected artisans the project grew within a span of two years increasing the number of skilled artisans to 30, thus helping in the formation of Producer Group.

SUJNI : Sujni Kanthas craft patches of different coloured cloth used are sewn together and then covered in designs to make a small quilt for newly-born babies. Rural women in Muzaffarpur produce furnishings such as bedspreads, wall hangings, and cushion and bolster covers, as well as clothing items like saris, dupattas. Most of the furnishing items are produced on cream markeen fabric using a combination of a fine running chain stitch with thread of different colours.

HONEY : Bee keeping is a seasonal activity which could be easily taken up by interested households as a source of generating additional income. This activity is being successfully being carried out in Muzaffarpur and Khagaria through communities involved in producer group.

JUTE : Purnea being a hub of jute cultivation was identified to initiate jute intervention. Members interested in jute rope making activity were brought into producer group fold to receive additional livelihood income.

Mr. Biplab Sarkar Manager Communication, Katihar

दीदी की कहानी दीदी की जुबानी

उम्मीद...

✍ श्री संतोष कुमार

"रौशन समूह से जुड़कर अपने को गौरवान्वित महसूस करती है और सिर्फ बीमारी ही नहीं बल्कि जिन्दगी की बाकी परेशानियों से लड़ने के लिए भी दूसरे महिलाओं को समूह से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।"

दिन भर की भाग–दौड़ में थक कर चूर अपने पैसों की थैली में चन्द सिक्कों की खनखनाहट उसकी आँखों में थोड़ी चमक तो ले आई थी लेकिन अगले ही पल न जाने क्या हुआ जो उसकी आँखें भर आयीं। एक पल को ऐसा लगा मानो ये सिक्कों की खनखनाहट से मिली खुशियों का असर है, लेकिन यहाँ बात कुछ और थी। उसकी आँखें उन सिक्कों की वजह से जरूर भर आयीं थीं लेकिन आंसुओं की असली वजह उन सिक्कों का उसकी उम्मीद से कम होना था।

"या अल्लाह...जाने तेरी क्या मर्जी है..." अपना मन मसोस कर बुदबुदाते हुए सब्जी की टोकरी अपने माथे पर रखते हुए रौशन अपने पति के साथ मंद कदमों से अपने आशियाने की ओर चल दी।

मोहल्ले की तंग गलियों से होते हुए अपने घर के दरवाजे पर पहुच कर दोनों ने एक दुसरे के सर से टोकरियाँ उतारीं और घर के अन्दर दाखिल हुए। खाट पे पड़ी बीमार सास और उसके ठीक बगल में रोते बिलखते दो बच्चे, दोनों के दोनों अपंग।

शादी के छः सालों के बाद जब शाजिया का जन्म हुआ और उसकी मानसिक अपंगता के बारे में पता चला तो रौशन अन्दर से टूट गयी थी। पहले से ही गरीबी और लाचारी ने जिन्दगी मुश्किल बना रखी थी ऊपर से औलाद की ऐसी हालत। इसे उपरवाले की मर्जी मानकर रौशन और उसके घरवालों ने उस नन्ही सी जान को अपने गले से लगाया और फिर से जिन्दगी काटने लगे। देखते– देखते दो साल गुजर गए और इसी बीच रौशन ने फिर से एक बच्चे को जन्म दिया। छोटा बेटा कौशाई का जन्म हुआ तो रौशन और उसके घरवालों को उम्मीद थी कि इस बार उपरवाला रहम करेगा और उनकी ये औलाद स्वस्थ होगी, लेकिन इस बार फिर वही हुआ और उसकी ये औलाद भी अपंग निकली। अब तो पूरा घर मानों बिखर सा गया।

"एक मुसीबत कम थी जो दूसरा भी वैसी ही तकदीर लेकर आ गया?" रौशन को अब हर रोज अपनी सास के ये ताने सुनने पड़ते।

पर वो तो माँ थी, चाहे जिस हाल में हों पर थे तो उसके ही बच्चे। उसने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखा और चल पड़ी अपने पति के साथ उसके काम–धंधे में हाथ बंटाने। अब उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। कमाई का कोई स्थायी जरिया नहीं था तो जाहिर है कि पेट भरने के लिए ढंग से खाना मुहैया भी नहीं हो पता था और शायद रौशन के जन्मे बच्चे की मानसिक स्तिथि का खराब होना इसी कुपोषण का फल था। खैर, अब जो भी था जैसा भी था जिन्दगी तो काटनी ही थी और जहाँ तक हो सके अपने बच्चे का इलाज करवाना भी जरूरी था। किसी तरह अपने पति के साथ घूम–घूम कर यहाँ–वहां काम करके दो पैसे इकट्ठे कर अपने बच्चों का इलाज करवाते रहे दोनों। पहले बेतिया फिर मोतिहारी फिर मुजफ्फरपुर, पटना और न जाने कहाँ–कहाँ भटकते रहे अपने बच्चों के इलाज की खातिर लेकिन जहाँ भी जाते बस एक ही जवाब मिलता कि इसे दिल्ली लेकर जाओ या फिर बंगलौर, यहाँ इनका इलाज नहीं हो सकता।

कहते हैं उपरवाले के घर में देर है अंधेर नहीं !! रौशन को एक रोज अपने मोहल्ले में कुछ औरतों कि भीड़ नजर आई जो एक समूह में बैठ कर कुछ बातें कर रही थीं। उत्सुकता में रौशन के कदम अपने आप उनकी तरफ मुड़ गए और वो उस समूह के पास जा खड़ी हुई। काफी देर तक उन सभी महिलाओं की गतिविधियों को देखती रही और ये समझने की कोशिश करती रही कि आखिर वहां हो क्या रहा था।

कुछ देर के बाद महिलाओं की सभा खतम हुई तो रौशन ने उन सभी महिलाओं से पूछ–ताछ शुरू की। बातों–बातों में पता चला कि सरकार ने

"रौशन की जिंदगी अब उम्मीदों से भर गयी है। जीविका से जुड़कर उसने वह पा लिया है जिसकी उम्मीद वह छोड़ चुकी थी।"

महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए "जीविका" परियोजना की शुरुवात की है जिसमे सभी महिलायें मिलकर एक समूह का निर्माण करती हैं और फिर आपस में बचत कर एक–दुसरे को आर्थिक सहयोग प्रदान करती हैं। सरकार भी इस तरह के समूहों को अपनी तरफ से कई तरह की सहायता प्रदान करती है और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई तरह से मदद करती है।

महिलाओं की बातें सुनकर रौशन की आँखों में एक चमक आ गयी और उसने बिना देर किये उस समूह में शामिल होने के लिए अपनी उत्सुकता जाहिर की। अब रौशन समूह से जुड़ कर धीरे–धीरे समूह में होने वाली हर गतिविधि को समझने लगी और थोड़े–थोड़े पैसों से समूह की बचत में अपना योगदान देने लगी। समूह से जुड़ने के तीन महीनों के बाद उसे यह जानकारी मिली कि सरकार की तरफ से समूह को प्रारंभिक निवेश निधि मिलनेवाली है जिसे समूह की सभी महिलाओं को उनकी जरूरत के हिसाब से कर्ज के रूप में आर्थिक मदद की जायेगी जिसके एवज में बहुत ही कम ब्याज देना होता है। रौशन ने अपनी नम आँखों से अपने बच्चों के इलाज के लिए पैसों की जरूरत का हवाला दिया और समूह की सभी सदस्यों ने भी उसकी इस बात का समर्थन किया द्य अब सूक्ष्म नियोजन पुस्तिका में रौशन का नाम सबसे ऊपर रखा गया और उसे 10 हजार रूपये का कर्ज देने का फैसला लिया गया।

दुसरे ही दिन रौशन अपने बच्चों और पति को साथ लेकर दिल्ली के लिए निकल पड़ी। देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान एम्स में उसने अपने बच्चों को दिखया और वहां के डॉक्टरों ने रौशन को वो खबर दी जिसका इंतजार न जाने वो कब से कर रही थी, "उसके बच्चे ठीक हो सकते थे"।

मायूस और नाउम्मीद हो चुकी रौशन खुशी के मारे उछल पड़ी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। डॉक्टरों की सलाह और कुछ दवाइयों के साथ रौशन बच्चों को लेकर वापस आ गयी और सबसे पहले ये खबर अपनी समूह महिलाओं को दी। इस खबर से सभी को प्रसन्नता हुई और सबने रौशन को बधाईयाँ दीं।

आज लगभग 3 साल बीत चुके हैं और रौशन के बच्चे धीरे–धीरे सामान्य हो रहे हैं। आज रौशन बड़े गर्व के साथ अपने समूह की हर गतिविधि का हिस्सा बनती है और सिर्फ बीमारी ही नहीं बल्कि जिन्दगी की बाकी परेशानियों से लड़ने के लिए भी दूसरी महिलाओं को समूह से जुड़ कर एकजुट होने को प्रोत्साहित करती है।

रौशन की जिन्दगी अब उमीदों से भर गयी है और "जीविका" से जुड़ कर उसने वो पा लिया है जिसकी उम्मीद उसने छोड़ दी थी। आज रौशन की जिन्दगी खुशहाल है और वो अपनी जिन्दगी में निरंतर आगे बढ़ रही है। ●

✍ **श्री संतोष कुमार**
संचार प्रबंधक, पश्चिमी चंपारण

बदलाव की बयार दियारा तक

"आज समूह से जुड़कर दियारा क्षेत्र की महिलाएँ भी जागरूक हो रही है। साथ ही साथ हस्ताक्षर करना भी जान गयी है। महिलाएँ समूह के साथ साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति सजग हो रही है एवं अनेक योजनाओं का लाभ ले रही है।"

✍ श्री संतोष कुमार

भागलपुर का एक प्रखंड खरीक गंगा एवं कोशी नदी के बीच अवस्थित है। प्रखंड की कुल आबादी 132898 है। प्रखंड में कुल 13 पंचायत एवं 35 गांव है। आधी से ज्यादा आबादी कोशी नदी के उस पार निवास करती है, जिसमें पंचायत लोकमानपुर और भवनपुरा आता है। लोकमानपुर पंचायत के अंतर्गत शिवकुंड और लोकमानपुर गांव आता है, तथा भवनपुरा पंचायत के अंतर्गत भवनपुरा, रतनपुर और मैरचा। जिसे दियारा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्र की कुल आबादी लगभग 11000 है। जिसमें पुरुष की संख्या 8350 एवं कुल 2650 महिलाएं निवास करती है। कुल परिवारों की संख्या 2200 है। कुल साक्षरता दर 45 प्रतिशत है जिसमें महिलाओं की साक्षरता का दर 40 प्रतिशत है। यह क्षेत्र साल भर में कुल चार महीनें पानी में डूबा रहता है। कहीं भी मुख्य शहर से आने जाने का रास्ता नहीं रह जाता है ऐसे में सिर्फ नाव से ही लोग अपनी मूल आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाहर निकलते हैं।

प्रखंड में जीविका परियोजना की शुरुआत 2 दिसंबर 2013 को हुई। अवागमन के आभाव व अपराध ग्रसित इलाके में कार्य करना काफी मुश्किल था। फिर भी दिनांक 1 फरवरी 2014 को दियारा क्षेत्र में परियोजना कार्य शुरू किया गया। परियोजना के बारे में जानकारी का आभाव तो था ही साथ ही स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का बुरा अनुभव भी लोगों के पास था जिससे जीविका पर सहज विश्वास करना आसान नहीं था। चन्दन कुमार, सामुदायिक समन्वयक के सूझ बुझ से दिनांक 5 फरवरी 2014 को वसंत पंचमी के दिन भीड़ इकठा करके आम सभा आयोजित किया गया, जिसमें परियोजना के बारे में बृहद जानकारी दी गई एवं इसके फायदे बताए गए। कुल 8800 परिवारों को लक्षित किया गया एवं सामुदायिक मोबलाईजर की पहचान कर प्रथम समूह "चन्दन जीविका स्वयं सहायता समूह'' का गठन किया गया। जाहिर सी बात है ऐसे क्षेत्र में समूह गठन के लिए सामुदायिक साधन सेवी को लाना मुश्किल था, फिर भी कार्यरत सिर्फ एक सामुदायिक समन्वयक के प्रयास से अब तक कुल 156 समूहों का गठन किया जा चुका है। जिसमें 1872 परिवारों को जोड़ा गया है।

प्रारंभ में दीदीयां प्रार्थना परिचय करने में शर्माती थी व आपस में जाति तथा वर्ग भेद भी चरम पर था। परन्तु अब स्वयं सहायता समूह के गठन होने से विभिन्न जाति समुदाय के लोग आपस में बैठने लगे जिससे मेलजोल की भावना व सामाजिक समरसता आई। यही नहीं समूह में नियमित रूप से बैठक, बचत व लेन देन भी हो रहा है।

सदस्य पूनम देवी के पास रहने लिए घर नहीं था, पति बीमारी से ग्रसित था, समूह में प्रारंभिक पूंजी नीधि कि राशी से 10000 का कर्ज लेकर गाय पालन शुरू की जिससे धीरे–धीरे आय का स्रोत बढ़ने लगा फिर सामुदायिक मोबलाईजर के रूप में चुनी गई। अब अपने परिवार के पांच सदस्यों का पालन पोषण भी बखूबी से कर रही है।

पहले वहां की महिलाएं हस्ताक्षर करना नहीं जानती थी परन्तु अब सी. एम एवं सी.सी के सहयोग से समूह की सभी महिलाएं हस्ताक्षर करना भी जान गई है। अभी तक कुल 8 ग्राम संगठन का भी गठन किया चुका है।

यही नही समूह व ग्राम संगठन की नियमित बैठक में बिभिन्न सरकारी योजनाओं का नियमित रूप से चर्चा किया जाता है। क्षेत्र से एक बैंक "बैंक ऑफ बड़ोदा" का जुड़ाव होने के बावजूद सरकार की जन धन योजना में 60 प्रतिशत दीदियों का खाता खोला गया। बैठक में "बेटी बचाओ बेटी पढाओ '' आदि जैसी योजनाओं का नियमित चर्चा से अब लड़कियां नियमित रूप से स्कूल जाने लगी है। दियारा क्षेत्र होने की वजह से पुलिस प्रशासन की पहुंच नहीं है जिससे अपराध की गतिविधियां होते रहती थी तथा लोगों में हमेशा भय व्याप्त रहता था । जिसका मुख्य कई कारणों में से एक शराब भी था। शराबबंदी लागू होने के उपरांत समूह की दीदियों द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया गया जिससे अपराध की संख्या में भी गिरावट आई।

क्षेत्र का मुख्य फसल मकई है। यहां के लोगों का मुख्य कार्य मकई का खेती करना एवं पशुपालन है। सदस्यों को आजीविका के अन्य साधनों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 15 सामुदायिक मोबलाईजर कार्यरत है एवं ग्राम संगठन के लिए दो बुक कीपर।

क्षेत्र में 2 उच्च विलय तथा 6 प्राथमिक विद्यालय है । विद्यालय में पठन पाठन की व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से नहीं होने के कारण बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं तो अब सभी दीदियों की नजर सरकार के नया निर्णय विद्यालय निरिक्षण पर टिकी है तथा स्कूल प्रबंधन कमिटी द्वारा स्कूल व्यवस्था में सुधार लाने को तत्पर है।

श्री संतोष कुमार
संचार प्रबंधक, भागलपुर

बड़की दीदी

✍श्री संतोष कुमार

✍ **श्री संतोष कुमार**
संचार प्रबंधक, प.चम्पारण

Bihar Rural Livelihoods Promotion Society (JEEViKA)

Bihar Rural Livelihoods Promotion Society, popularly known as "Jeevika" was constituted in 2005 under the aegis of RDD / Government of Bihar with the objectives of social and economic empowerment of rural poor. The major objectives being,

- **Improving rural livelihoods** and enhancing social and economic empowerment of the rural poor.
- **Developing organizations of the rural women** and producers to enable them **to access and better negotiate services, credit and assets from public and private sector agencies and financial institutions.**
- Playing a catalytic role in promoting **development of microfinance, agribusiness sectors and health nutrition and sanitation services.**

Jeevika has been successful in generating significant development impact in the areas of inclusive social mobilization, financial inclusion and livelihoods strengthening and diversification. It is also designated as the State Rural Livelihoods Mission (SRLM) for implementing NRLM in the state.

Promotion of strong and sustainable community institutions of poor has clearly emerged as a key strategy to combat rural poverty in Bihar. as on 2017, nearly 76 lakh households have been mobilized into more than 6.49 lakh Self-Help Groups and their federations. These exclusively women based institutions are highly inclusive with high participation of Scheduled Caste and Scheduled Tribes households. The institutional platform of SHGs and higher federations has enabled the rural poor to mobilize internal resources from within the community while also ensuring better access to financial services from the formal sector. More than 3042 crores have been leveraged from formal financial sector and Bihar has emerged as a shining beacon in SHG- Bank Linkage especially in eastern India where banks have traditionally been reluctant to lend to institutions of the poor.

The SHGs are widely viewed as the ideal platform for efficient targeting and delivery of various social welfare programs and have shown promise in delivering long term behavior change critical in achieving higher outcomes in the areas of health, nutrition and sanitation. Also, the institutional platform has proven to be effective in streamlined delivery of livelihood services. Mobilization of farmer households into Producer Organizations has also proved to be effective in strengthening the production systems by better delivery of inputs and extension services while also enhancing the capacity of small farmers to productively engage with prevailing market systems.

The newly approved Bihar Transformative Development Project will aim at scaling up JEEViKA's institutional model in the entire state. In line with the emerging priorities and JEEViKA's already significant experience, the new project will have a special focus on improved nutrition and sanitation outcomes in the project areas and will also leverage technical support from specialist agencies for next generation outcomes across farm and non-farm value chains. The project will reach to 45 lakh households in six years, making Bihar the leading state in India in terms of mobilization of rural women into community institutions. The six-year project with World Bank financing to the tune of INR2700 Crores, in 300 Blocks across 32 District.

Mrs. Mahua Roy Chaudhury
Programme Coordinator
Governance & Knowledge Management

मन की कलम से

चला जीविका का रथ

हरी क्यारियों में, खेतों में फसलें लहराएँ
मिले पेटभर भोजन सबको, शिशु शिक्षा पाएँ
हर मौसम वसन्तय–सा, सबके मन उत्साह–भरे
धरती पर गन्दगी, तिमिर का लेश न रह पाए।

बहे नेह की सरिता सबका समरस जीवन हो
लदी फलों से हर डाली, सुरभित हर उपवन हो
मिल जुलकर आगे बढ़ने का भाव रहे मन में
खुशहाली से भरे गाँव, हर घर, हर आँगन हो।

ऊँचे पर्वत पर चढ़ विजय पताका फहराएँ
अपने पथ पर बिना रुके हम बढ़ते ही जाएँ
बढ़ता रहे कारवाँ, हम जाएँ न ठहर थक कर,
पहुँच लक्ष्य तक गीत खुशी के मिलजुल हम गाएँ।

आर्य भगीरथ के पथ पर हम चलते जाएँगे
हम उतार नभ से खुशियों की गंगा लाएँगे
मिहनत को सम्मान मिलेगा, कलुष दूर होगा
दूध–भात ले चन्दा मामा घर–घर आएँगे।

चला जीविका का रथ अविरल बढ़ता जाएगा
मंजिल तक पहुँचेगा, पथ में ठहर न जाएगा
गति अबाध इसके पाँवों की, शाश्वात बनी रहे
कालपत्र पर चरण–चिह्न अंकित कर जाएगा।

मद्य निषेद्य लगा, विकास का पथ आसान हुआ
लगता सुख आनेवाला, दुख का अवसान हुआ
नित नूतन खुशियाँ ले प्रात सुनहली आएगी
सबके सपने मुस्काएँगे, ऐसा भान हुआ।

● श्री ब्रजकिशोर पाठक
विशेष कार्य पदाधिकारी, जीविका

Flowers shall Bloom

I play and smile
And enjoy my dreams for awhile
My mother with bleeding fingers,
picking up shared of shattered dreams-
Seldom smiles
But whenever she does so
The pang of hunger twitches her lips
Radiating stark truth of life
Her smile betrays agony and grief
I see the Flowers in her eyes wilt
And gradually melt into fire
No, I am not a child any more
I won't let her smile turn wry; I won't let flowers die
I'll hold your hands as you will hold others'
And others'tight
We shall unite and fight
With demons of insecurity,
Insensitivity and loss of faith in unity!
Self-help is the greatest help one can fetch
Together we would discover our identity
And march ahead forging our destiny
Our thousand hands, strong and skilled enough
Shall lift the Sun up the horizon and tear the clouds that
Shade the rays of hope
We shall make things happen
We won't let our mother die, in despair, with tears in eyes
The smile would be wider
And flowers shall bloom in thousands eyes.

● **Shri K. Anshumaly**
Director, JEEViKA

Training of Block Project Managers on Project Management

National award for outstanding performance of RSETI at National RSETI Diwas 2017

National award for outstanding performance in SHG Bank Linkage

Launching of Newsletter of JEEViKA

जीविका

जीविका

NATIONAL

बिहार सरकार

JEEViKA

Rural Development Department,Govt. of Bihar
Vidyut Bhawan - II,1st Floor, Bailey Road, Patna- 800 021;
Ph.:+91-612-250 4981 :: Fax : +91-612-250 4960,
Website : www.brlp.in :: E-mail : ceo@brlp.in